



वी. चेट्टियार

कार्यकारी संपादक
8898800908

हिन्दी साप्ताहिक

RNI No.: MAHHIN/2023/89178

एकता केसरी™

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 23 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 04 to 10 July 2025 • Price 5/- • Page 8

अंकुल भारत गैस वितरक के अवैध ट्रक गोदाम पर क्यों नहीं होता कार्रवाई – राशनिंग विभाग के आशीर्वाद से फल फूल रहा

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या प्रशासन शिवडी ग्रांड डिपो क्षेत्र में अवैध रूप से भरे हुए गैस सिलेंडरों को रखने के लिए भारी वाहन ट्रक गोदाम बनाने वाले अंकुल.भारत. गैस वितरक के खिलाफ कार्रवाई करेगा? मुंबई पिछले कुछ महीनों में, गैस सिलेंडरों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उदाहरण के लिए, धारावी बस डिपो के पास एक अवैध गैस सिलेंडर गोदाम में बनाए गए एक भारी वाहन में विस्फोट से मानव जीवन नहीं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, प्रशासन और कंपनी ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुंबई क्षेत्र में निवारक उपाय के रूप में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि अंकुल.भारत गैस वितरक ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और भारत पेट्रोलियम कंपनी को गुमराह करके शिवडी ग्रांड डिपो क्षेत्र में अवैध रूप से भरे हुए गैस सिलेंडर गोदाम की स्थापना की है। वे प्रशासन के किसी भी विभाग से अनुमति लिए बिना या



■ गैस वितरक अंकुल भारत पर कब होगी कड़ी कार्रवाई –या प्रशासन कर रही बड़ी दुर्घटना का इंतजार?

■ भारत गैस कंपनी और राशनिंग विभाग के अधिकारी क्यों बने सुरक्षा कवच ? मिलता है मोटी मलाई?

किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय किए बिना उपरोक्त व्यवसाय कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस कारण से, भविष्य में कोई भी दुर्घटना होने पर पास के ईस्ट फ्री रोड को भी नुकसान होगा। अटल सेतु, सड़कें और पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। यात्रा करने वाले यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) वितरकों के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के

सख्त विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। P.E.S.O विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C.A.), 1955, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 का पालन नहीं करता है। अंकुल गैस एजेंसी बीपीसीएल कंपनी के अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और अंकुल गैस एजेंसी को कम कीमत पर गैस बेचने की पूरी अनुमति देते हैं।

धनजी स्ट्रीट –शेख मेमन स्ट्रीट –खाऊगली –यूसुफ मेहर अली रोड –दादीशेट अग्यारी लेन – अब्दुल रहमान स्ट्रीट –भास्कर गली भूलेश्वर रोड सब जगह पर अवैध फेरीवालों का कब्जा

- ❖ इन अवैध फेरीवालों को बैठाने में कहीं एल.टी मार्ग पुलिस या मनपा सी वार्ड का तो हाथ नहीं?
- ❖ खाऊ गली –शेखमेमन स्ट्रीट –धनजी स्ट्रीट –अब्दुल रहमान स्ट्रीट के अवैध फेरीवालों ने बताया कि एल. टी मार्ग पुलिस –मनपा सी वार्ड को देते हैं महीने में लाखों रुपया हफ्ता/यह बात कही हकीकत तो नहीं?
- ❖ अखबार वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते –हमलोग
- ❖ एल.टी मार्ग पुलिस तथा मनपा सी वार्ड को देते हैं मजबूत हफ्ता –डीसीपी जोन 2 के मोहित गर्ग भी कुछ नहीं कर सकते।

मुंबई एक तरफ अवैध फेरीवालों से रास्ते बंद हैं और मनपा सी वार्ड –तथा एल टी मार्ग पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी है लेकिन चुनौती तो है लेकिन देखा जाय तो यह फेरीवाले एल टी मार्ग पुलिस तथा मनपा सी वार्ड के

अतिक्रमण विभाग के सुख सुविधा का जरिया भी है। इसलिये अवैध फेरीवाले अपना कब्जा जमाये बैठे हैं और एकबाई एक की at जगह 5मीटर बाई पांच मीटर में बैठे हैं जिसमें हर एक पुलिस वाले की कमाई हो रही है इसी का नमूना है धनजी



स्ट्रीट –खाऊ गली –शेखमेमन स्ट्रीट –दादी सेठ अग्यारी लेन – अब्दुल रहमान स्ट्रीट –भास्कर गली –भूलेश्वर रोड जहा पर चलने की जगह नहीं है इन सब फेरीवालों के खिलाफ त्रस्त होकर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि मुंबई के सारे अवैध फेरीवालों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त

किया जाय –लेकिन कोर्ट के आदेश की आड़ में मनपा सी वार्ड के अतिक्रमण विभाग ने धनजी स्ट्रीट –खाऊ गली –शेख मेमन स्ट्रीट –दादी सेठ अग्यारी लेन –भास्कर गली–अब्दुल रहमान स्ट्रीट –भूलेश्वर रोड इन सब जगह के अवैध फेरीवालों को कार्यवाही की धौंस दिखाकर अपना हफ्ता बढ़वा लिया

हफ्ता बढ़ जाने के बाद कार्यवाही के नाम पर जीरो मनपा सी वार्ड का अतिक्रमण विभाग कोई कार्यवाही करता ही नहीं है तथा एल.टी मार्ग पुलिस सिर्फ फेरीवालों को 1200 रुपये का दण्डमार कर छोड़ देती है। लेकिन यह विकल्प नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है कि अवैध फेरीवाला नहीं चाहिये अतिक्रमण

मुक्त चाहिये यानी जगह क्लियर चाहिये एक भी फेरीवाला बैठने ना पाये –बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश नहीं है की एल. टी मार्ग पुलिस सिर्फ 1200 रुपया दंडमार कर छोड़ दे अपना कोटा पुर कर ले। इसलिये –धनजी स्ट्रीट –शेख मेमन स्ट्रीट –खाऊ गली –भास्कर गली – अब्दुल रहमान स्ट्रीट –भूलेश्वर इन सब जगह के अवैध फेरीवालों को तुरंत हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाय तथा खाऊ गली 3री अग्यारी लेन के फेरीवालों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाय। अब देखना यह है कि एलटी मार्ग पुलिस दंड मारकर छोड़ देती है यह फेरीवालों को हटाती है? इसलिये एल.टी मार्ग पुलिस अपनी छवि साफ रखने के लिये फेरीवालों को हटाती है या नहीं।

संपादकीय

श्रद्धा और संकल्प की यात्रा, अमरनाथ यात्रा आतंक के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही

जम्मू-कश्मीर की हिमालय पर्वत श्रृंखला में 13,000 फुट पर स्थित महादेव का तीर्थ समस्त तीर्थों का सार है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या के पश्चात आपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर एक बड़ा संकेत दिया था। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर को दशकों पीछे धकेलने की भी साजिश थी। इसलिए इस साल की तीर्थयात्रा जम्मू-कश्मीर के सपनों को नया अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष यात्रा से पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा कि भारत न केवल जम्मू-कश्मीर के तीव्र विकास के लिए समर्पित, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकियों के अंत के लिए भी दृढ़-संकल्पित है। छह जून को कटरा में भी वही संकल्प नजर आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का लोकार्पण कर संदेश दिया था कि अब भारत की प्रगति के पहिये नहीं थमेंगे और आतंकियों के संहार के साथ-साथ विकास का तीव्र प्रसार भी होता रहेगा। जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ाव के साथ ही यहां 70 साल से भेदभाव से ग्रस्त समाज को मुख्यधारा में लाया गया। पिछले पांच वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के संकल्प ने राज्य की दशा-दिशा बदली है। औद्योगिक निवेश तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्याकल्प हुआ है। सभी के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। शासन ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। ऊर्जा, वित्तीय संसाधन, कृषि एवं किसान, शिक्षा, युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ने जम्मू-कश्मीर को बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान की है। वक्त ने करवट बदली है और अब आम कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे संयम और धैर्य के साथ जम्मू कश्मीर को आतंक-मुक्त करने के प्रयासों की अहम भूमिका रही है। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पाकिस्तान के खिलाफ वादी की सड़कों पर आम नागरिकों का गुस्सा इसका संकेत है कि जम्मू-कश्मीर अपनी नई भाग्य रचना कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में कश्मीर घाटी में बच्चे राष्ट्रगान की गूंज सुनते हुए बड़े हुए हैं। नई पीढ़ी की चेतना अतीत के बोझ से मुक्त है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जो बदलाव अर्जित किया, वह इस केंद्रशासित प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर तथा जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भव्यतम रूप देकर प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में नई गौरवगाथा लिखी है। सपनों और सुविधाओं में फासला कम हुआ है। उज्ज्वल भविष्य की आतुरता ही अब जम्मू-कश्मीर की ताकत है। व्यापक परिवर्तन अमरनाथ यात्रा के आयोजन में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। 2024 में पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे। 12 वर्षों में तीर्थयात्रा का यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो लैंडफिल दृष्टिकोण अपनाया गया है। आज देश भर के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक समारोहों के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। 2022 से 2024 के बीच यात्रा मार्गों पर काफी सुधार कार्य किए गए हैं। पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों पर 12 फीट तक चौड़ा यात्रा मार्ग बनाया गया है। इन मार्गों पर रियल टाइम निगरानी रखने तथा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं के लिए आरएफआईडी-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जरूरी

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे, तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अलग-अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951 और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति 'गायब' हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख

व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबेंस्राम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से भारत की किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स बनाई थीं। इनमें से एक टास्क फोर्स बार्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष माधव गोडबोले थे, जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अगस्त 2000 में भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि देश में हर पार्टी में इस समस्या के प्रति उदासीनता थी और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने साफ लिखा कि इस समस्या को लेकर सारी जानकारी और उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन थे, पर राजनीतिक वर्ग में समस्या से निपटने के तरीकों में कोई 'सहमति' न होने के कारण निष्क्रियता रही। टास्क फोर्स के आकलन के अनुसार हर महीने करीब 25 हजार यानी प्रतिवर्ष तीन लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे और भारत में उनकी कुल संख्या उस समय तक करीब 1.5 करोड़ थी। बांग्लादेश-भारत सीमा पर जैसे-जैसे फेंसिंग लगती गई, घुसपैठियों की संख्या में कमी होती गई। फिर भी बांग्लादेशी

घुसपैठियों की संख्या भारत में इस समय कम से कम दो करोड़ होगी। 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वह देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में एक फैसले में कहा कि असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल-पुथल और विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस परिस्थिति में भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि असम की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई करे। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली और स्थिति जस की तस बनी रही। क्या यूपीए सरकार, क्या एनडीए सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और शेख हसीना वहां से बचकर भारत में निर्वासित रूप में रह रही हैं और मोहम्मद यूनस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है, जो भारत विरोधी है, तब सबको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। समकालीन वैश्विक परिदृश्य को देखें तो तमाम देश अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न देशों से घुसपैठ कर आए हुए सभी व्यक्तियों को जबरन उनके देश वापस भेजा जा

रहा है। पाकिस्तान ने भी करीब 13 लाख अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। मलेशिया से भी बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे माहौल में भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों और म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। फिलहाल विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि हम शायद कुछ हजार बांग्लादेशियों को ही वापस भेज पाएंगे। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में रहने की स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली, अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों को अलग पहचान पत्र दिए जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें देश में रहने और काम करने की अनुमति हो। दूसरी, वे भारत में अचल संपत्ति न खरीद सकें और तीसरी उन्हें किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार न हो। भारत सरकार को यह भी साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कारिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी। गृहमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी घुसा चला आए और यहीं बसेरा बना ले।

क्वाड का संदेश, आतंकवाद पर चीन और अमेरिका आदि देशों का दोहरे रवैया

अमेरिका में चार देशों के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह तो कहा गया कि पहलगाम में आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। स्पष्ट है कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के रवैये से भारत संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अमेरिका की पहल पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। आखिर उसकी ओर संकेत करने का क्या अर्थ? क्या पाकिस्तान क्वाड के सदस्य देशों से भी बड़ा देश है अथवा ऐसी कोई आर्थिक एवं सैन्य ताकत है, जिससे आतंकी संगठनों को पालने पोसने की उसकी नीति की

आलोचना-निंदा करने में संकोच किया जाए? इस संकोच के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वार्थ जान पड़ते हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारत की सैन्य कार्रवाई पर जिस तरह प्रतिकूल रवैया अपनाया, उससे भारत को तो हैरानी हुई ही, स्वयं अमेरिका की आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति नए सिरे से उजागर हुई। यह साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को प्रिय और महान देश बताने के साथ पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की तारीफ भी की। इसके कारण कुछ भी हों, भारत

को आतंकवाद के मामले में अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की नीति से सावधान रहना चाहिए। भारत को इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने होंगे कि क्वाड जिन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया, उनके अनुरूप ही कार्य करे और ऐसा करते हुए सभी सदस्य देशों के हित की चिंता करे। भारत इस पर संतोष कर सकता है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के अतिरिक्त जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई, वे उसके हितों को रेखांकित करने और उसकी चिंताओं को अभिव्यक्ति देने वाले हैं। कुछ समय बाद क्वाड शिखर सम्मेलन होना है। भारत को अभी से इस बैठक की तैयारी करनी होगी। इसी के साथ उसे

अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से चीन की भी सदस्यता वाले एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में वैश्विक हितों के साथ अपने हितों की चिंता करनी ही होती है। यह शुभ संकेत है कि पिछले कुछ समय से भारत अपने हितों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी मुखर हुआ है। यह मुखरता इसलिए कायम रहनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र केवल बातें करने का मंच बनकर रह गया है। भारत को आतंकवाद के मामले में चीन, अमेरिका आदि देशों के दोहरे रवैये को बार-बार रेखांकित करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया का खरगे पर पलटवार, कहा- कांग्रेस के साथ भारत का बफरिंग युग खत्म



कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्र सरकार पर डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में झूठे दावे और अधूरे वादे करने का आरोप लगाया था। इसका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। वहीं पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे होने पर एक ब्लॉग साझा किया।

डिजिटल इंडिया मिशन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का बफरिंग युग कांग्रेस के शासन के साथ समाप्त हो गया है। देश अब पीएम

मोदी के नेतृत्व में 5जी में स्थानांतरित हो गया है। खरगे ने केंद्र सरकार पर डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में झूठे दावे और अधूरे वादे करने का आरोप लगाया था।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे आपको ज्ञान देने का एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब भी आपने अतीत में हमसे सवाल किए हैं, हमने परिणामों के साथ जवाब दिया है।

वर्षों तक जबकि आपकी पार्टी ने डायल-अप वादे किए, हमने जमीनी स्तर पर और बड़े पैमाने पर एक विश्व स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क, UPI, आधार और

भारतनेट का निर्माण और वितरण किया।

जन आंदोलन बन चुका है डिजिटल इंडिया

इससे पहले डिजिटल इंडिया मिशन की दसवीं वर्षगांठ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक लिंकडइन हैंडल पर डिजिटल इंडिया का एक दशक शीर्षक से एक ब्लॉग साझा किया। उन्होंने लिखा कि दस साल पहले, हमने एक ऐसे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी यात्रा शुरू की थी, जहां पहले कोई नहीं गया था। जहां दशकों तक यह संदेह किया गया कि भारतीय तकनीक का उपयोग कर पाएंगे या नहीं, हमने उस सोच को बदला और भारतीयों

की तकनीक उपयोग करने की क्षमता पर विश्वास किया। जहां दशकों तक सिर्फ यह सोचा गया कि तकनीक का उपयोग अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेगा, हमने उस मानसिकता को बदला और तकनीक के माध्यम से उस खाई को खत्म किया।

डिजिटल इंडिया की नींव बना- एक ऐसा मिशन, जो सभी के लिए पहुंच को लोकतांत्रिक (आसान) बनाने, समावेशी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ। वर्ष 2014 में, इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी, और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बेहद सीमित थी।

कई लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। आज, इस प्रश्न का उत्तर डाटा और डैशबोर्ड में नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन के माध्यम से दिया जा चुका है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन-देन व निर्माण तक, डिजिटल इंडिया हर जगह है।

'बार-बार बोलने के बाद भी फार्मा कंपनी ने नहीं बदली थी पुरानी मशीनरी', एफआईआर में खुलासा



शिकायत यशवंत राजानाला ने दर्ज कराई है, जिसके पिता राजानाला वेंकट जगन मोहनवास सिगाची कंपनी में बीते 20 वर्षों से कर्मचारी थे। यशवंत ने बताया कि 'उसके पिता ने कई बार हमें बताया था कि मशीनरी पुरानी हो गई है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।' तेलंगाना में फार्मा कंपनी में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें बताया गया है कि कर्मचारियों द्वारा बार-बार बोलने के बावजूद फार्मा कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पुरानी हो चुकी मशीनरी को नहीं बदला। कंपनी की पसामयलाराम स्थित यूनिट में दो दिन पहले तेज विस्फोट हुआ था, जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 33 लोग घायल हैं।

सांगरेडु पुलिस ने पीड़ितों और उनके परिजनो की शिकायत के आधार पर सोमवार को कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, 'शिकायतकर्ता के पिता और अन्य कर्मचारियों ने सिगाची कंपनी प्रबंधन को कई बार मशीनरी बदलने के बारे में सूचना दी गई थी, क्योंकि मशीनरी बहुत पुरानी थी और उनसे जान-माल की हानि की आशंका थी। हालांकि कंपनी प्रबंधन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पुरानी मशीनरी का ही इस्तेमाल जारी रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि प्लांट में विस्फोट हो गया, जिससे जान-माल की भारी हानि हुई।' शिकायत यशवंत राजानाला ने दर्ज कराई है, जिसके पिता राजानाला वेंकट जगन मोहनवास सिगाची कंपनी में बीते 20 वर्षों से कर्मचारी थे। यशवंत ने बताया कि 'उसके पिता ने कई बार हमें बताया था कि मशीनरी पुरानी हो गई है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।'।

'कोई अनबन नहीं, सिद्धारमैया के नेतृत्व में मतभेद की भी जगह नहीं', शिवकुमार ने अटकलों पर लगाया विराम



पार्टी के कुछ नेताओं की हालिया टिप्पणियों से एक बार फिर इस वर्ष के अंत में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगने लगी हैं। बीते कुछ समय से राजनीतिक हलकों में, खास तौर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर चर्चा हो रही है कि इस साल के अंत में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। हालांकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व और कर्नाटक कांग्रेस ने इस सभी चर्चाओं को खारिज किया है और किसी भी मतभेद से इनकार किया है। कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों सीएम पद फिर चर्चा में है। चर्चा हो रही है कि शीर्ष पद के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में मतभेद है। साथ ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग भी हो रही है। हालांकि कर्नाटक प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहले ही इन चर्चाओं पर विराम लगा चुके हैं।

मनोजीत को नियमों का उल्लंघन कर संविदा कर्मचारी नियुक्त किया गया; दुष्कर्म केस की जांच जासूसी विभाग को

केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, 'TMC एक कॉलेज कैंपस को सुरक्षित नहीं रख पा रही है अगर कॉलेज कैंपस में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है तो आपकी शिक्षा प्रणाली और कानून-व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न उठता है। ममता बनर्जी स्वयं कह चुकी हैं कि यह एक छोटी घटना है। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार गंभीर नहीं है।'

कोलकाता लॉ कॉलेज दुष्कर्म के मुख्य आरोपियों में से एक मनोजीत मिश्रा को बुनियादी नियमों का उल्लंघन कर उसी कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बीच खबर है कि मामले की जांच का जिम्मा जासूसी विभाग



संभालने जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ महीने पहले जब कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजीत की नियुक्ति का प्रस्ताव गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के समक्ष रखा गया था तो आठ गवर्निंग बॉडी सदस्यों में से केवल चार ने ही उस नियुक्ति को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया था। नियम यह है कि अस्थायी नियुक्तियों के लिए गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी की

आवश्यकता होती है।

सूत्रों के मुताबिक, आठ गवर्निंग बॉडी सदस्यों में से चार मनोजीत की नियुक्ति के खिलाफ थे, क्योंकि मनोजीत का आपराधिक रिकॉर्ड था।

उस पर गुंडागर्दी, गंभीर नुकसान पहुंचाना और कॉलेज परिसर में यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लग चुके हैं। हालांकि, इसके बावजूद गवर्निंग बॉडी के एक प्रभावशाली सदस्य के आग्रह के बाद उनकी

नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मनोजीत उस सदस्य को कथित तौर पर चाचा कहकर संबोधित करते थे।

मनोजीत की नियुक्ति रद्द, दोनों छात्र भी निष्काशित

दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मनोजीत की संविदा नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह भी तय किया गया है कि आरोपी को अंतरिम अवधि के दौरान प्राप्त वेतन वापस करना होगा। मामले में दो अन्य आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय (लॉ कॉलेज के वर्तमान छात्र) को संस्थान से निष्काशित कर दिया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि मनोजीत की नियुक्ति को कैसे मंजूरी दी गई?

'नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रशासन में केवल भ्रम पैदा हुआ', पी. चिदंबरम का अमित शाह पर पलटवार



अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के एक साल पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि नए कानून में 90 दिन में जांच, चार्जशीट और फैसले की समयसीमा तय की गई है, जिससे लोगों में 'एफआईआर से तुरंत न्याय' मिलेगा, ऐसा विश्वास बढ़ेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इन कानूनों को लागू करने को 'कट एंड पेस्ट' एक्सप्रसाइज बताया। चिदंबरम ने कहा कि तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू करना व्यर्थ का काम है। इनसे न्यायाधीशों, वकीलों और पुलिस के बीच न्याय प्रशासन में केवल भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। पी चिदंबरम ने यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नए आपराधिक कानूनों के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में

इन्हें स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा सुधार करार दिए जाने पर दिया है। बीते दिन, राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि नए आपराधिक कानूनों से न्यायिक प्रक्रिया न केवल सस्ती और सुलभ होगी, बल्कि सरल, समयबद्ध और पारदर्शी भी होगी। चिदंबरम ने आपराधिक कानूनों को लेकर कसा तंज

सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने बार-बार दावा किया है कि तीन आपराधिक कानून विधेयक, जो अब अधिनियम बन चुके हैं, आजादी के बाद के सबसे बड़े सुधार हैं, लेकिन यह सच से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति को अपना असहमति नोट भेजा था। इतना ही नहीं यह संसद में पेश की गई रिपोर्ट में भी शामिल है। अपने असहमति नोट में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं की तुलना संबंधित नए विधेयक से

करने के बाद, मैंने कहा था कि यह केवल कट-पेस्ट एक्सप्रसाइज है। नए विधेयक में आईपीसी का 90-95%, सीआरपीसी का 95% और साक्ष्य अधिनियम का 99% हिस्सा काट-छांट कर शामिल किया गया है।

क्या बोले थे अमित शाह

अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के एक साल पूरे होने पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि नए कानून में 90 दिन में जांच, चार्जशीट और फैसले की समयसीमा तय की गई है, जिससे लोगों में 'एफआईआर से तुरंत न्याय' मिलेगा, ऐसा विश्वास बढ़ेगा। गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग अध्याय बनाया गया है और आतंकवाद व संगठित अपराध पर सख्त सजा का प्रावधान है।

नए कानून का 14.80 लाख पुलिसकर्मियों, 42 हजार जेल कर्मियों और 19 हजार जजों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि 160 बैठकों और 89 देशों की न्याय प्रणालियों के अध्ययन के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया। उन्होंने जोर दिया था कि जनता को अपने अधिकारों की जानकारी जरूरी है, ताकि ये कानून आजादी का सबसे बड़ा सुधार बने। गौरतलब है कि बीते साल एक जुलाई को तीनों नए आपराधिक कानून लागू हुए थे। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली थी।

नगर निगम अफसर हमले के विरोध में कर्मचारी संगठन, सामूहिक अवकाश पर गए अधिकारी, कामकाज प्रभावित

सोमवार को भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू से कुछ बदमाशों ने उनके कार्यालय से घसीटकर उनके साथ मारपीट की थी। हमले के मामले में पुलिस ने अब तक भाजपा पार्षद जीवन राउत सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले को लेकर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है।

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) में वरिष्ठ अधिकारी पर हमले को लेकर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है। हमले के विरोध में ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएसएस) और ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) के नेतृत्व में अधिकारी सामूहिक अवकाश पर



चले गए हैं। इसके चलते राज्य के सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया है। सोमवार को भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू से कुछ बदमाशों ने उनके कार्यालय से घसीटकर उनके साथ मारपीट की थी। हमले के मामले में पुलिस ने अब तक भाजपा पार्षद

जीवन राउत सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले के विरोध में ओएसएस एसोसिएशन ने सामूहिक अवकाश का आह्वान किया था।

लेकिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने इसे स्थगित कर दिया था। ये भी पढ़ें: कंपनी ने तेलंगाना

फार्मा प्लांट विस्फोट में 40 मौतों की पुष्टि की, एक-एक करोड़ के मुआवजे का भी एलान इसके बाद भी कटक, गंजम, गजपति, कंधमाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, संबलपुर, बोलनगीर, सोनपुर, रायगढ़ा, ढेंकनाल और मयूरभंज सहित अधिकांश जिलों में ओडिशा प्रशासनिक सेवा और ओडिशा राजस्व सेवा के अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। एक अधिकारी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण राज्य में सरकारी एवं सार्वजनिक सेवा कार्य लगभग ठप हो गए हैं।

'वह जननेता हैं', सिद्धारमैया पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायक की सफाई



कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर की गई टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि उनके पास जनता का भारी समर्थन था। पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने मेरी बातों को तोड़-मड़ोकर कर पेश किया है। उन्होंने बताया कि मैं केआर पेते में अपने एक प्रिय मित्र से बात कर रहा था, जब सिद्धारमैया का विषय उठा। मैंने तब कहा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने के मामले में जैसे लॉटरी जीत गए हों। यह कहना गलत है कि मैंने उन्हें सोनिया गांधी से मिलने के लिए कहा था। मैं तो बस उस समय उनके साथ था जब वे सोनिया गांधी से मिलने गए थे। इस बार तो वे सोनिया गांधी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरे दबाव के बाद उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। वह एक जननेता हैं। मेरे पास उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। सिद्धारमैया की नियुक्ति को प्रभावित करने के आरोपों को खारिज करते हुए पाटिल ने कहा कि कुल लोग जानबूझकर उनके साथ मेरे रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

कंपनी ने तेलंगाना फार्मा प्लांट विस्फोट में 40 मौतों की पुष्टि की, एक करोड़ के मुआवजे का भी एलान



तेलंगाना के संगारेड्डी में सोमवार को एक फार्मा प्लांट में संदिग्ध विस्फोट हुआ था। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब कंपनी ने मौतों की पुष्टि की है। साथ ही मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का एलान किया है।

तेलंगाना के पशाम्यलारम में फार्मा प्लांट में हुए विस्फोट में सिगाची इंडस्ट्रीज ने 40 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। कंपनी ने मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का एलान किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम दुख के साथ तेलंगाना कारखाने में हुई दुर्घटना की जानकारी साझा कर रहे हैं। इस हादसे में हमारी टीम के 40 सदस्यों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हो गए।

कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के बाद से ही हम आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवार सहायता का समन्वय कर रहे हैं। इसके अलावा जांच और अनुपालन प्रयासों में सहयोग दे रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि घायलों को पूर्ण चिकित्सा और पुनर्वास सहायता मिलेगी। कंपनी ने कहा कि यह दुर्घटना प्लांट में रिएक्टर विस्फोट के कारण नहीं हुई। हम इसकी जांच के बाद सही जानकारी देंगे। तब तक प्लांट में 90 दिनों के लिए परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा। फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा

विस्फोट पीड़ितों में से एक के परिवार के सदस्य की शिकायत के आधार पर संगारेड्डी पुलिस ने सोमवार को फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (हत्या के बराबर नहीं) 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

राज्यों के संगठन चुनाव के बाद सुलझेगी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गुत्थी; उत्तर प्रदेश पर भी मंथन जारी

उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष के मामले में विमर्श का दौर बीते तीन दिनों से जारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को पांच और बुधवार को चार राज्यों में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विमर्श का दौर तेज हो गया है। मध्य जुलाई तक नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्यों में संगठन चुनाव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को मिजोरम और पुदुचेरी में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हुआ है।



मंगलवार को पांच और बुधवार को चार राज्यों में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। चूंकि मिजोरम और पुदुचेरी में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में अगले दो दिनों में 25 राज्यों को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी नया प्रदेश अध्यक्ष तय करना चाहती है। हालांकि खास कर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले इन राज्यों में भी

नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन जाएगी। प्रधानमंत्री के 8 दिवसीय यात्रा संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विमर्श का दौर शुरू होगा। इन राज्यों में हुआ नामांकन कार्यकारी अध्यक्ष सोमवार को उत्तराखंड में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल, आंध्रप्रदेश में पीवीएन माधवन, तेलंगाना में रामचंद्र राव और महाराष्ट्र में वर्तमान रवि चव्हाण ने नामांकन किया है। इकलौते नामांकन के कारण इनका अध्यक्ष बनना तय है। इसकी घोषणा मंगलवार को की जाएगी। इस बीच सोमवार को डॉ के बैडचुआ मिजोरम और दीपी

रामालिंगम को पुदुचेरी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

आज इन राज्यों में नामांकन इन सात राज्यों के अतिरिक्त चार राज्यों मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव व लद्दाख में मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। इन राज्यों में नए अध्यक्ष की घोषणा बुधवार को की जाएगी। पार्टी की कोशिश बुधवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में इस पद के लिए नामांकन कराने की है। इन राज्यों के संदर्भ में बैठकों का दौर जारी है।

यूपी पर फैसले के बाद ही होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की योजना जुलाई के मध्य और मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले हर हाल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। चूंकि वहां कई स्तर पर अहम बदलाव होने हैं, ऐसे में इस राज्य के संदर्भ में कई स्तर पर विमर्श हो रहा है।

सिंधु समझौता स्थगित करने के फायदे बताएगा केंद्र, पांच राज्यों में कांग्रेस को घेरने के लिए खास रणनीति



केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में कांग्रेस को घेरने के लिए खास रणनीति बनाई है। इसके तहत केंद्र सरकार किसानों को सिंधु समझौता स्थगित करने के फायदे बताएगी। कांग्रेस ने किया अन्याय अब किसानों को मिलेगा न्याय अभियान के तहत शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और सीआर पाटिल किसानों को बताएंगे कि समझौता स्थगित करने के बाद कैसे इससे जुड़ी नदियों के पानी का उनके राज्यों में खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। भाजपा और मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता के मामले में उत्तर भारत के पांच राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और सीआर पाटिल इन राज्यों में किसान संवाद और अभियान के जरिये समझौता स्थगित किए जाने का लाभ गिनाने के साथ ही यह भी बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार ने 1960 में कैसे इन राज्यों के किसानों पर पाकिस्तान को तरजीह दी थी। इस दौरान तीनों मंत्री इस समझौते में शामिल नदियों का भारत की भूमि पर उपयोग की योजना की भी जानकारी देंगे। कांग्रेस ने किया अन्याय अब किसानों को मिलेगा न्याय अभियान के तहत ये मंत्री इन राज्यों के किसानों को बताएंगे कि समझौता स्थगित करने के बाद कैसे इससे जुड़ी नदियों के पानी का उनके राज्यों में खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। इस दौरान सरकार यह भी बताएगी कि कैसे नेहरू सरकार के कार्यकाल में अन्यायपूर्ण तरीके से इन नदियों के पानी का 80 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। इस अभियान के जरिए सरकार इस कथित अन्यायपूर्ण समझौते को उत्तर भारत के राज्यों के बीच जारी जल विवाद का कारण बताएगी। सरकार ने सिंधु समझौता रद्द करने के साथ ही इससे जुड़े नदियों के पानी को उत्तर भारत के उपरोक्त राज्यों में उपयोग की दीर्घकालिक योजना बनाई है। इसके तहत सरकार की योजना 160 किमी की नई नहर के जरिए चेनाब नदी को रात्री, ब्यास और सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ने की है। सिंधु नदी को अन्य नदियों और नहरों से जोड़ने के लिए 13 किमी की लंबी सुरंग बनाई जानी है।

आईपीएस विकास कुमार का निलंबन रद्द, सीएटी ने निलंबित अफसरों को दी बड़ी राहत

चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बीते चार जून को मचे भगदड़ मामले में निलंबित आईपीएस विकास कुमार को बड़ी राहत मिली है। सीएटी ने मंगलवार को उनका निलंबन रद्द कर दिया और सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया। सीएटी की तरफ से रोका गया ये निलंबन अन्य निलंबित अधिकारियों की बहाली का रास्ता भी खोल सकता है।



को उनका निलंबन रद्द कर दिया। बता दें कि मामले में बंगलुरु बेंच के जस्टिस बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य संतोश मेहरा की पीठ ने 24 जून को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। सीएटी ने विकास कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें सेवा नियमों के तहत सभी लाभ मिलेंगे।

सीएटी ने निलंबन को बताया अवैध आईपीएस अधिकारी विकास

कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने बताया कि सीएटी ने निलंबन को अवैध ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया है और अधिकारी को सभी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। सात ही सीएटी ने यह भी कहा कि इस फैसले का लाभ तत्कालीन पुलिस कमिशनर बी दयानंद और डीसीपी शेखर एच. टेप्पेन्नावर को भी मिल सकता है, जिससे उनकी बहाली का रास्ता खुल गया है।

आरसीबी की जीत के जश्न में मची

भगदड़

गौरतलब है कि आरसीबी की जीत के जश्न में 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित 'विजय रैली' में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई थी। आरसीबी के सीईओ ने 3 जून को पुलिस कमिशनर को ईमेल के जरिए कार्यक्रम की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से समय की कमी बताते हुए कोई औपचारिक जवाब नहीं भेजा गया। सरकार का आरोप था कि पुलिस को भारी भीड़ की संभावना पहले से पता थी, फिर भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।

न तो सार्वजनिक सूचना जारी की गई, न ही भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। उच्च अधिकारियों से भी मार्गदर्शन नहीं लिया गया।

यूएई ने भारतीयों को दिया आगमन वीजा विस्तार का तोहफा, कहा दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध



यूएई दूतावास ने बताया कि जिन भारतीय पासपोर्ट धारकों के पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर का वैध निवास परमिट है, वे अब यूएई के सभी प्रवेश बिंदुओं पर वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले, भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल तभी मिलता था जब उनके पास अमेरिका, यूरोपीय संघ या ब्रिटेन का वैध वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड होता था।

भारतीय नागरिकों के लिए संयुक्त अरब अमीरात के आगमन पर वीजा कार्यक्रम का विस्तार भारत के साथ उसकी स्थायी साझेदारी का प्रतिबिंब है। यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने कहा कि इस नीति से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

'जिम्मेदारी थी, सोचता था बस कहीं से पैसा आ जाए...', गोविंदा को लेकर पहलाज निहलानी ने किया खुलासा



गोविंदा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में दी हैं। इन फिल्मों में 'हीरो नंबर 1', 'राजा बाबू' और 'आंखें' शामिल हैं। इसके अलावा भी कई फिल्मों में उनके रोल और डांस यादगार हैं। हालांकि इन दिनों उनके स्क्रीन से दूर होने की वजह से उनके फैंस निराश हैं। कई लोगों का कहना है कि गोविंदा थोड़ा घमंडी हैं इसलिए उनके करियर में डाउनफॉल आया है। उनके

एटीट्यूड की वजह से निर्देशक और निर्माता उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने बताया है कि गोविंदा के साथ क्या दिक्कत है। अनिश्चितता से भरे हुए थे गोविंदा लर्न फ्रॉम द लीजेंड पॉडकास्ट से बातचीत में पहलाज निहलानी ने बताया 'गोविंदा हर चीज को लेकर अनिश्चितता से भरे हुए थे। उनके

पिता महबूब खान के चहेते थे। वह फिल्म निर्माता भी थे। उन्हें कई बार नुकसान हुआ। उन्होंने इतना दर्द सहा, फिर भी बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकल गईं और संघर्ष करना पड़ा। यह सभी चीजें उनके अंदर बस गईं। इसलिए उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया था। गोविंदा के आयोजन की तैयारी में जुटे समाजजन गोविंदा जैसा एक्टर नहीं मिलेगा उन्होंने गोविंदा के बारे में कहा 'उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से पैसे आ जाएं। उनके पास भाई बहनों की जिम्मेदारियां थीं। वह पैसों में उलझे रहते थे। वह सब कुछ करना चाहते थे। उनका नजरिया ही ऐसा हो गया था। उनके पास काम और दबाव बहुत था। वह

वह भी हो गए थे। यह सारी चीजें उनको खाती रहीं। हालांकि आपको गोविंदा जैसा एक्टर नहीं मिलेगा।' पहलाज निहलानी ने की गोविंदा की मदद पहलाज निहलानी ने गोविंदा के बारे में कहा 'उसने शोला और शबनम' में काम किया। उस वक्त उनके पास कोई काम नहीं था। जब उनके पास कोई काम नहीं था, तब मैंने उन्हें 'शोला और शबनम' फिल्म दी। वह इसमें पहली बार कॉमेडी कर रहे थे। फिर उनके पास कोई काम नहीं था तब मैंने उन्हें फिल्म 'आंखें' दीं। मैंने उनकी छवि बदली। 'शोला और शबनम' और 'आंखें' दोनों एक दूसरे की विपरीत हैं। मैंने उन्हें उस रोल के काबिल बनाया।'

एजबेस्टन में जब पिछली बार हुई थी टक्कर तो बुमराह ने ब्रॉड को धो डाला था, एक ओवर में बटोरे थे 35 रन

भारत और इंग्लैंड के बीच आज से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी। हालांकि, प्लेइंग-11 को लेकर अभी भी कुछ तय नहीं है। कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिख सकते हैं। अगर बुमराह खेलते हैं तो एजबेस्टन में भारतीय टीम को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि 2022 में उन्होंने इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी की थी। वह मौजूदा टीम में उन 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें इस मैदान का अनुभव या वह पहले भी भारतीय टीम के साथ इस मैदान पर अभ्यास कर चुके हैं। 2022 में जब बुमराह ने पिछली बार एजबेस्टन में खेला था तो उन्होंने बल्ले से कमाल किया था। बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को धो डाला था और विश्व रिकॉर्ड बना डाला था। 2022 में बुमराह ने ब्रॉड को धोया था दरअसल, पिछली बार जब भारत ने 2022 में एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बटोरे थे, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में बटोरे गए सर्वाधिक रन हैं। इस दौरान बुमराह ने ओवर की



आधिकारिक तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर चौका बटोरा था। पांचवीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था और आखिरी गेंद पर एक रन आया था। दूसरी गेंद से पहले ब्रॉड ने दो और गेंद फेंके थे। इसमें से एक वाइड थी जो चार रन के लिए गई थी और दूसरी नो बॉल थी, जिस पर बुमराह ने छक्का लगाया था। इस तरह ब्रॉड के ओवर से बुमराह ने 35 रन बटोरे थे। इस ओवर के बाद ब्रॉड खुद यकीन नहीं कर पाए थे कि एक पुछल्ले बल्लेबाज ने उन्हें इतना धोया है। ब्रॉड इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से हैं। उनकी गिनती इंग्लैंड के महान गेंदबाजों में होती है। भारत को हार का सामना करना पड़ा हालांकि, भारत को 2022 एजबेस्टन टेस्ट में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

इंग्लैंड ने टेस्ट इतिहास का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था। उन्होंने बेयरस्टो और रूट के शतकों के दम पर 378 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। बुमराह की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 146 रन और रवींद्र जडेजा ने 104 रन की पारी खेली थी। वहीं, ब्रॉड की धुनाई करने वाले बुमराह ने 16 गेंद में चार चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 31 रन बनाए थे। जेम्स एंडरसन ने पांच विकेट लिए थे। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई थी। बेयरस्टो ने 106 रन बनाए थे। भारत के लिए सिराज ने चार और बुमराह ने तीन विकेट लिए थे। शमी को दो विकेट मिले थे। बेयरस्टो और रूट ने हाथ से छीना दूसरी पारी में भारत 132 रन की

बढ़त के साथ उतरा था। भारतीय टीम की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई थी। पुजारा ने 66 और पंत ने 57 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स ने चार विकेट, जबकि ब्रॉड और पॉट्स को दो-दो विकेट मिले थे। भारत की इंग्लैंड पर कुल बढ़त 377 रन की हुई थी और 378 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड ने 76.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। एलेक्स लीस ने 56 रन, जैक क्रॉउली ने 46 रन की पारी खेली थी। इसके बाद जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने 269 रन की नाबाद साझेदारी कर इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। बेयरस्टो ने नाबाद 114 रन और रूट ने नाबाद 142 रन बनाए थे। भारत के लिए बुमराह ने दो विकेट लिए थे। इस तरह इंग्लैंड ने पांचवां टेस्ट ड्रॉ कराया और सीरीज भी 2-2 से बराबर कराई। अब टीम इंडिया की बारी है। बुमराह और रूट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। एजबेस्टन में किन भारतीय ने शतक लगाए एजबेस्टन में शतक लगाने वाले भारतीयों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा जैसे नाम शामिल हैं। सचिन और कोहली अब टेस्ट में नहीं खेलते हैं, जबकि पंत और जडेजा इस बार भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी के पिता का हुआ निधन, सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट



बॉलीवुड की एक्ट्रेस मंदाकिनी के पिता का बुधवार को निधन हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह जानकारी देते हुए मंदाकिनी ने अपने पिता की एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि पिता के निधन से उनका दिल टूट गया है।

मंदाकिनी ने पिता को लेकर लिखी भावुक पोस्ट

मंदाकिनी ने अपनी पोस्ट में पिता की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'मेरा दिल चूर-चूर हो गया है। आज सुबह मेरे पिता का निधन हो गया है। इस जुदाई के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आपके बेइतिहा प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद पापा। आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे।' आपको बता दें कि मंदाकिनी ने बुद्धिस्ट मोंक डॉ०. कांग्युर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी की है। वह तिब्बत हर्बल सेंटर चलाते हैं। दोनों से दो बच्चे हैं। उनका एक लड़का है जिसका नाम रब्बल है और लड़की है जिसका नाम रब्जे इन्नाया है। दलाई लामा की फॉलोवर बनने के बाद मंदाकिनी तिब्बती योग क्लास चलाती हैं।

दाऊद से रिश्ते को लेकर चर्चा में रहीं

मंदाकिनी 1990 की दहाई के शुरुआती वर्षों में दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुक को लेकर सुर्खियों में रही हैं। यही नहीं मंदाकिनी दुबई में दाऊद इब्राहिम के साथ नजर भी आईं। मंदाकिनी ने यह कुबूल किया कि वह दाऊद से मिलीं लेकिन उन्होंने उनके साथ रिश्ते में होने की बात से इंकार किया। मंदाकिनी के दाऊद से ताल्लुक की वजह से उनके करियर पर प्रभाव पड़ा।

मंदाकिनी की बॉलीवुड फिल्में

मंदाकिनी को सबसे ज्यादा शोहरत 1985 में आई फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में काम करने के बाद मिली। फिल्म का निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया था। फिल्म में उनके साथ लीड रोल में राजीव कपूर थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसमें 'डांस डांस', 'कहां है कानून' और 'प्यार करके देखो' शामिल हैं।

'शमी ने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा, इतना प्यार करती थी कि मैं तैयार हो गई', हसीन जहां का बयान



भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां का कहना है कि वह शादी से पहले मॉडल थीं और अभिनय करती थीं। गेंदबाज ने उन्हें यह पेशा छोड़ने को कहा और उन्होंने

उनकी बात मान ली। बता दें कि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को उनके साथ चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता दें। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया। हसीन जहां का बयान इस आदेश के बाद हसीन जहां का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि शादी से पहले वह मॉडलिंग करती थीं, लेकिन शमी ने उन्हें गृहिणी बनकर जीने के लिए कहा।

प्लास्टिक से हो रहा प्रदूषण हमारे जीवन लिए बहुत बड़ा खतरा, जानिए कैसे करें बचाव

मौजूदा समय में प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

हर छोटी-छोटी चीज को रखने के लिए हम प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करते हैं। लगातार बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण मनुष्यों से लेकर जीव-जंतुओं तक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है।

आसानी से उपलब्ध हो जाने और टिकाऊ होने के चलते हम प्लास्टिक और उससे बनी चीजों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी इसके खतरों के बारे में नहीं जाना-समझा, तो इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

प्लास्टिक के इन खतरों से अवगत कराने के उद्देश्य से हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। जिसके जरिए लोगों को प्लास्टिक के अलावा अन्य चीजों अपनाए की सलाह दी जाती है, जिससे पर्यावरण को बचाने में सहयोग मिल सके। आइए जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए प्लास्टिक स्ट्रॉ को कहीं ना प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट या कहीं बाहर जूस या शेक पीने के लिए अगर



प्लास्टिक स्ट्रॉ को दुकानदार दें, तो उसे साफतौर से मना कर दें। सीधे ग्लास से पिएं या फिर अगर पेपर स्ट्रॉ हो, तो उसे इस्तेमाल करें। गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश का मौसम अपने साथ प्लास्टिक की बॉटल की जगह

ग्लास की बोतल कैरी करें। सस्तेबल शॉपिंग करें आज पैकेजिंग से लेकर कपड़ों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक में प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको शॉपिंग पर भी

लगाम कसने की जरूरत है। ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें, जिनका आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएं और जिनसे वो वातावरण के भी अनुकूल हो।

लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल अगर आप पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं तो अपने डे टू डे की लाइफ में जहां-जहां पॉसिबल हो, लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल करें। इसकी शुरुआत आप टूथब्रश और कंघी से कर सकते हैं। बाथरूम में प्लास्टिक की वस्तुओं को लकड़ी से बनी चीजों से रिप्लेस करें।

कपड़े या जूट का बैग इस्तेमाल करें प्लास्टिक प्रदूषण रोकने की शुरुआत

आप कपड़े या जूट के बैग के इस्तेमाल से कर सकते हैं। इससे काफी हद तक प्लास्टिक की खपत को रोका जा सकता है। अपने बैग में कपड़े का झोला रखें और सब्जी हो या दूसरी चीजों की खरीददारी के लिए इसे ही यूज करें।

साबुन का करें इस्तेमाल बॉडी वॉश या जेल आपको बाथिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बना सकते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके लिए हर साल 4 लाख से ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, तो साबुन से नहाना शुरू करें।

क्यों ट्रंप से तनाव के बीच सियासी दल बनाने को तैयार मस्क, डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'बिग ब्यूटीफुल बिल' सीनेट में पारित हो गया है। सरकारी खर्चों को बढ़ाने से जुड़ा यह विधेयक ट्रंप और दुनिया सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के रिश्ते बिगड़ने की वजह भी है। मस्क इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब एलन मस्क ने कहा है कि अगर 'बिग ब्यूटीफुल बिल' पारित हो जाता है, तो उसके अगले ही दिन एक 'अमेरिकन पार्टी' का गठन किया जाएगा।

आखिर एलन मस्क की ट्रंप से नाराजगी की मुख्य वजह क्या है? उनकी तरफ से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह एक स्थायी तीसरी पार्टी बनाने के प्रस्ताव में कितना दम है? क्या अमेरिका में इस तरह के प्रयास पहले हुए हैं? ये प्रयास कितने सफल रहे? किसी पार्टी के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जगह लेना मुश्किल क्यों है? आइये जानते हैं...

एलन मस्क की ट्रंप से नाराजगी की वजह क्या है?

एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव अभियान में करीब 30 करोड़ डॉलर (लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये) तक खर्च किए थे। दोनों की दोस्ती ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी जारी रही और मस्क को सरकारी खर्चों में कटौती की जिम्मेदारी के साथ सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि, ट्रंप ने जब 'बिग ब्यूटीफुल बिल' के जरिए अमेरिका में कई व्यवस्थाओं को बदलने की मंशा



जताई तो मस्क ने इसका विरोध किया। आलोचकों ने भी इसे लेकर कई चिंताएं जाहिर की हैं। मसलन इस विधेयक में लोगों को मिलने वाले हेल्थकेयर प्लान को या तो कमजोर किया जा रहा है या लोगों से इसकी व्यवस्था ही छीनी जा रही है। इसके अलावा यह विधेयक अगर कानून बनता है तो ट्रंप की नई योजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने की वजह से अगले दशक तक अमेरिका का कुल कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर (करीब 3172 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

मस्क का कहना है कि ट्रंप सरकार का नया विधेयक अगर कानून बनता है तो इससे अमेरिकी नागरिकों पर कर्ज और बढ़ जाएगा और राष्ट्रपति का वह वादा, जिसमें उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती करने की बात कही थी, उसका मकसद भी नाकाम हो जाएगा। ट्रंप अपनी योजना के तहत कानून बनाकर अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा के लिए मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को भी कम करने या खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क इसे लेकर ट्रंप से सबसे ज्यादा नाराज हैं। दरअसल, मस्क की वाहन कंपनी

टेस्ला, स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित कार और ट्रक बनाती है। इस कंपनी को अमेरिकी सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के तहत फायदा मिलता है। मस्क नई अमेरिकी पार्टी बनाने के प्रस्ताव को लेकर कितने गंभीर? एलन मस्क की तरफ से अमेरिका में नया राजनीतिक दल बनाने का प्रस्ताव नया नहीं है। पिछले महीने ट्रंप से विवाद के बीच उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सर्वे कराया था। इसमें 80 फीसदी लोगों ने उनके नई पार्टी बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तब मस्क ने कहा था कि यह अमेरिका में दो पार्टियों के सिस्टम से लोगों का मोहभंग होने का संकेत है। मस्क ने कहा है कि वह ट्रंप के विधेयक का समर्थन करने वाले लगभग सभी रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ अगले चुनाव में किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देंगे। मस्क ने कुछ नेताओं का खुले तौर पर समर्थन शुरू भी कर दिया है। इनमें अमेरिका के केंटकी से सांसद थॉमस मैसी का नाम शामिल है, जिन्होंने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का खुलकर विरोध किया है।

क्या अमेरिका में कोई पार्टी तोड़ सकती है रिपब्लिकन-डेमोक्रेटिक

पार्टी का वर्चस्व?

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो अमेरिका में सबसे लंबे समय से ग्रांड ओल्ड पार्टी के नाम से लोकप्रिय-रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखा है। इसी के चलते अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली को ट्रू पार्टी सिस्टम यानी दो पार्टियों की प्रणाली से जोड़कर देखा जाने लगा है। हालांकि, अमेरिका ट्रू पार्टी सिस्टम वाला देश नहीं रहा है। अमेरिकी चुनाव की एन्साइक्लोपीडिया कही जाने वाली वेबसाइट बैलटपीडिया के मुताबिक, जनवरी 2025 तक अमेरिका में 55 ऐसी पार्टियां हैं, जो एक साथ कई राज्यों में बैलट पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। वहीं, राज्य स्तर पर 238 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी को बैलट पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कम से कम 10 राज्यों में मौजूदगी दर्ज करानी होती है। इस लिहाज से जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम ही सभी 50 राज्यों के बैलट पर मौजूद हैं। वहीं, तीन और ऐसी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानी जाती हैं। बताया जाता है कि ग्रीन पार्टी का एजेंडा पर्यावरण के मुद्दों पर केंद्रित होता है। वहीं, लिबरटेरियन पार्टी, जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वह नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की कम भूमिका होने की वकालत करती है और सिर्फ उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ही दखल को तवज्जो देती है।

न्यूयॉर्क चुनाव में गरमाई सियासत, ट्रंप ने ममदानी को बताया 'कम्युनिस्ट पागल'



अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को 'कम्युनिस्ट पागल' और 'खतरनाक इंसान' करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ममदानी मेयर बनते हैं तो वह न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे और वह ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ और न्यूयॉर्क को किसी कम्युनिस्ट पागल के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरे पास सारे अधिकार और विकल्प हैं। मैं न्यूयॉर्क को फिर से महान और जीवंत बनाऊंगा, जैसा मैंने अमेरिका के साथ किया था।' ममदानी ने दिया करारा जवाब

इस बयान पर जोहरान ममदानी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ने खुलेआम मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने और मुझे डिटेनशन सेंटर में डालने की धमकी दी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) एजेंसी को लोगों पर आतंक फैलाने से रोकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह बयान लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

ममदानी ने खुद को बताया न्यूयॉर्क का सच्चा प्रतिनिधि ममदानी ने कहा कि ट्रंप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई आवाज न उठा सके। उन्होंने कहा, 'अगर आप बोलेंगे, तो वे आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मैं न डरने वाला हूँ और न झुकने वाला। न्यूयॉर्क में हर शख्स को बिना डरे जीने का अधिकार है।' जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और उनका जन्म युगांडा में हुआ था। उनके माता-पिता दक्षिण एशिया से हैं। अगर वह जीतते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। उन्होंने हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मेयर पद का टिकट हासिल किया है।

सड़क कंक्रीटीकरण में अब तक नौ ठेकेदारों पर 38.93 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया

मुंबई: जून 2022 में, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कार्यभार संभाला था, मुंबई की सड़कों को "गड्ढा मुक्त" बनाने के लिए मेगा कंक्रीटीकरण परियोजना की योजना की घोषणा की थी। अक्टूबर 2023 में महत्वाकांक्षी मेगा सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना के शुरू होने के बाद से, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर भर में कामों को निष्पादित करने के लिए लगाए गए सभी नौ ठेकेदारों पर देरी, खराब गुणवत्ता आदि जैसी खामियों के लिए 38.93 करोड़ रुपये का संचयी जुर्माना लगाया है। हालांकि, काम में देरी का खामियाजा शहर के पूर्वी उपनगरों को भुगतना पड़ रहा है, जहां ठेकेदार - ईगल इंफ्रा - पर लगभग 17 करोड़ रुपये का सबसे अधिक जुर्माना लगाया गया है, जून 2022 में, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने मुंबई की सड़कों को रगड़ा मुक्त बनाने के लिए मेगा कंक्रीटीकरण परियोजना की योजना की घोषणा की। घोषणा के बाद, नागरिक निकाय ने 17,733 करोड़ रुपये की लागत से शहर भर में लगभग 700 किलोमीटर सड़कों को कंक्रीट करने के लिए दो चरणों में कार्य आदेशों के लिए निविदाएं जारी कीं और ठेके दिए। निर्धारित कुल सड़क लंबाई में से, 320 किमी

(700 सड़कें) को चरण I में कंक्रीट किया जाना है, जबकि 378 किमी सड़कें (1,421 सड़कें) चरण II में ली जानी हैं। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना में नौ एजेंसियों को कार्य आदेश दिए गए हैं - चरण 1 के कार्यों के लिए चार ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है और चरण 2 के लिए पांच ठेकेदारों को शामिल किया गया है, मार्च 2023 में पहले चरण के लिए निविदाएं प्रदान किए जाने के बाद, अक्टूबर 2023 तक मानसून की वापसी के बाद परियोजना पर काम शुरू हो गया। एकटेकसरी द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 से मई 2025 के बीच, सभी ठेकेदारों पर कुल 38.93 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 33.71 करोड़ रुपये चरण 1 के तहत जुर्माना लगाया गया है जबकि 5.22 करोड़ रुपये चरण 2 के ठेकेदारों पर लगाया गया है। इसके अलावा, 17 करोड़ रुपये के साथ, नागरिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सबसे अधिक जुर्माना ईगल इंफ्रा इंडिया पर लगाया गया था, जिसे पहले चरण में पूर्वी उपनगरों में सड़कों को कंक्रीट करने के लिए लगाया गया था। नागरिक निकाय के अनुसार, देरी से काम करने के कारण जुर्माना लगाया गया था। परिप्रेक्ष्य के लिए, चरण 1 में पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में सड़क

- अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर की कड़ी कार्रवाई।
- उपनगरों के कंक्रीटीकरण में हुये भ्रष्टाचार, खराब गुणवत्ता वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कब ? होगी कड़ी कार्रवाई, मुंबईकर



कंक्रीटीकरण के लिए कार्य आदेश शामिल हैं, जबकि द्वीप शहर प्रभाग में कंक्रीटीकरण का अनुबंध चरण 2 में दिया गया था। अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने बताया कि समय सीमा में देरी, काम शुरू करने से पहले निविदा की शर्तों का पालन न करने, काम की खराब गुणवत्ता समेत अन्य कारणों से जुर्माना लगाया गया है। बांगर ने कहा, 'जहां भी हमने

खामियां देखीं, सभी ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, लेकिन जुर्माने का बड़ा हिस्सा पहले चरण में लगाया गया है। दूसरे चरण में जुर्माना बहुत कम है क्योंकि दूसरे चरण का काम अक्टूबर 2024 के बाद ही शुरू हुआ था। बीएमसी खराब गुणवत्ता वाले काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। जहां भी हमने अपने निरीक्षण के दौरान खराब गुणवत्ता वाला काम देखा है,

हमने तुरंत जुर्माना लगाया है और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। काम की गुणवत्ता में खामियों की चिंताओं और रिपोर्टों को दूर करने के लिए, बांगर सहित वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आरएमसी संयंत्रों के साथ-साथ कार्यस्थलों का औचक दौरा किया था। वर्तमान में, मानसून के मौसम के कारण

परियोजना पर नागरिक कार्य रोक दिए गए हैं, जबकि शेष कार्य अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद बारिश के खतम होने के बाद शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक, नागरिक डेटा से पता चलता है कि मुंबई की 700 किलोमीटर सड़कों को कंक्रीट करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य का लगभग 49 प्रतिशत हासिल किया गया है। पहले चरण में, बीएमसी ने 101.67 किलोमीटर सड़कों (या 343 सड़कों) को पूरी तरह से कंक्रीट करने और 101.68 किलोमीटर को आंशिक रूप से पूरा करने के साथ लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया है। इस बीच, दूसरे चरण में, 31 मई तक लक्ष्य का 36 प्रतिशत हासिल किया गया है, जिसमें 84.33 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से कंक्रीट की गई है। बांगर ने कहा कि हालांकि मानसून के कारण अब काम रुका हुआ है, लेकिन बीएमसी ने आने वाले महीनों में कार्यों के निष्पादन के लिए चरणबद्ध योजना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 'हम अपनी योजनाओं को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार अधिक सक्रिय होने के साथ-साथ लोगों के प्रति जवाब देही भी हों।

फिर गुंजा किसान आत्महत्या का मुद्दा, इस साल 767 मौतें, सरकार चर्चा के लिए तैयार

मुंबई: किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में तीसरे दिन भी छाया रहा। बुधवार को विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर जमकर आड़े हाथों लिया। किसानों की आत्महत्या का वादा बहुत अच्छा है कहते हुए विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बीते 3 महीनों में राज्य में 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नौबत ऐसी आ गई है कि बैलों के अभाव किसान खुद को हल में जोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद सरकार किसानों की कर्जमाफी का वादा भूल गई है, ऐसा



आरोप लगाते हुए विपक्ष ने चर्चा की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने कहा कि विपक्ष पक्षाघात प्रस्ताव लाए, मैं चर्चा के लिए पूरा दिन देने को तैयार हूँ। लेकिन

विपक्ष किसानों की समस्या की आड़ में राजनीति न करे। लेकिन चर्चा की मांग तुरंत स्वीकार नहीं होने पर विपक्ष ने दो बार विधानसभा से दो बार बहिर्गमन किया। किसानों की

आत्महत्या और सोयाबीन खरीद के लिए कथित तौर पर भुगतान नहीं किए जाने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार घेरने का जोरदार प्रयास किया। तीन महीनों

में 700 से अधिक मौत विधानसभा में कांग्रेस नेता विजय वडेटीवार ने दावा किया कि इस वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्य में 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया, जिसमें शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को गोवा को नागपुर के साथ जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वडेटीवार ने कहा कि प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं और

फिर भी सरकार उदासीन बनी हुई है। इस साल जनवरी से मार्च तक, 767 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से 200 मामलों को (मृतक के परिजन के वास्ते) सहायता के लिए अयोग्य घोषित किया गया जबकि 194 मामलों में अभी भी पूछताछ लंबित है। उन्होंने सरकार पर चुनाव से पहले कर्ज माफी और लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोयाबीन और कपास उत्पादकों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिला है।